भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3117

उत्तर देने की तारीख 20 मार्च, 2023

सोमवार, 29 फाल्गुन, 1944 (शक)

भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों का कौशल विकास

3117. श्री रमेश बिन्द:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी कौशल विकास योजनाएं शुरू की गई हैं और पूरी की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों के लिए कौशल विकास केन्द्र खोला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कौशल विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आबंटित कुल धनराशि का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश भर में विभिन्न स्कीम अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

एमएसडीई की स्कीमों के अंतर्गत, सभी प्रशिक्षण केंद्रों में दिव्यांग व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोला गया है। तथापि, दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने और दिव्यांगों के अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) में प्रशिक्षण देने के लिए दिव्यांग कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी) नामक दिव्यांगों के लिए एक विशेष क्षेत्र कौशल परिषद है। ऐसे केंद्रों को संरचनात्मक रूप से तैयार किया गया है ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को आसानी से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

(घ) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 455.39 करोड़ रुपए और जेएसएस के अंतर्गत 79.37 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश राज्य को पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात 2019-20 से दिसंबर, 2022 तक जारी की गई है। साथ ही, आईटीआई के संबंध में दैनिक प्रशासन और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। एनएपीएस के अंतर्गत, प्रतिष्ठानों को वृत्तिका सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है

****